

प्रेषक,

जयदेव सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्श,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 13 दिसम्बर, 2013

विषय- उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा के अधिकारियों के विभिन्न भत्तों/सुविधाओं में वृद्धि किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-6751/XVII-7/Admin.A/2013 दिनांक 04-12-2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0- 54 एक(1)/XXXVI(1)/ 2006-06 एक (2)/06 दिनांक 25.08.2006 तथा शासनादेश सं0- 108 /XXXVI(1)/2010-50/2009 दिनांक 21.05.2010 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के स्वीकृत वेतन भत्तों में कतिपय संशोधन करते हुए निम्नलिखित वेतन भत्तों में वृद्धि किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. समाचार पत्र एवं पत्रिका:- इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0- 54 एक(1)/XXXVI(1)/ 2006-06(एक)(2)/06 दिनांक 25.08.2006 द्वारा प्रत्येक माह में 02 पत्रिकाओं हेतु अनुमन्य धनराशि रू0 50/- के स्थान पर रू0 150/- (रू0 एक सौ पचास मात्र) प्रतिमाह होगी।

2. पोशाक भत्ता:- प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को प्रत्येक 02 वर्ष में रू0 6000/- के स्थान पर रू0 10,000/- (रू0 दस हजार मात्र) की धनराशि पोशाक भत्ते के रूप में अनुमन्य होगी।

3. वाहन ईंधन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता:- सभी न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक जनपद में प्रतिमाह 100 लीटर पेट्रोल/डीजल मासिक की सीमा तक अनुमन्य होगा।

4. वर्दी धुलाई भत्ता:- प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को वर्दी धुलाई भत्ता रू0 300/- प्रतिमाह के स्थान पर रू0 1000/- (रू0 एक हजार मात्र) प्रतिमाह अनुमन्य होगा।

5. बाहय न्यायालय भत्ता:- प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को बाहय न्यायालय भत्ता रू0 150/- प्रतिमाह के स्थान पर रू0 1,500/- (रू0 एक हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह अनुमन्य होगा।

6. ड्राईगरूम का सुसज्जीकरण:- उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा/न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक 06 वर्ष में रू0 75,000/- (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आवास पर ड्राईग रूप के सुसज्जीकरण हेतु अनुमन्य होगी।

क्रमशः.....2

3- उक्त भत्तों/सुविधाओं से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत शासनादेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं०-168NP/XXVII(5)/2013 दिनांक 13.12.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जयदेव सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या- 385(1)/XXXVI(1)/2013-6 एक(2)/06 टी0सी0 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराँय भवन, माजरा देहरादून।
- 2- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23- लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 3- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, सविचालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
- 6- निबन्धक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, श्रम न्यायालय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- 7- अध्यक्ष, उत्तराखण्ड व्यापार कर अधिकरण, हरिद्वार रोड, रिस्पुना पुल से पहले देहरादून।
- 8- अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, देहरादून।
- 9- सचिव, लोकायुक्त, 218-किशननगर (सिरमौर मार्ग), कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 10- निबन्धक, राज्य उपाभोग्ता प्रतितोष आयोग, प्रथम तल, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिला न्यायालय परिसर, देहरादून।
- 11- सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड नैनीताल।
- 12- निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल।
- 14- महाप्रशासक, उत्तराखण्ड, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 15- अपर सचिव (विधि), उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार।
- 16- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 17- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 18- एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मनीष मिश्र)
अपर सचिव